



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

विधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 1971/माघ 9, 1892

No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 1971/MAGHA 9, 1892

---

इस भाग में भिन्नपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

---

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND  
CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January 1971

G.S.R. 152.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service in the Food Corporation of India, established under the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), would prejudicially affect the maintenance of supplies and services necessary for the life of the community and would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares service in the Food Corporation of India to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. F.10-3/70-FCC/Vol.II.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी 1971

सा० का० नि० 152 :—आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) को धारा 2 को उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार यह राय होने के कारण कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम की किसी भी सभा में हड़ताल होने से सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हे समुदाय के लिए भारी कठिनाई पैदा होगी, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावजनों के लिए भारतीय खाद्य निगम को सेवा का आवश्यक सेवा घोषित करती है ।

[न० फा० 10-3/70 एफ० सी० सी० खण्ड II]

आर० एस० तलवाड़,  
संयुक्त सचिव ।